जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 80 प्रभात जालोर, बुधवार 26 जून, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

अमित शाह, नड्डा, रिजिजू के साथ ओम बिड़ला लोकसभा महासचिव के कार्यालय पहुँचे, अपना पर्चा दाखिल कराने

कांग्रेस की ओर से केरल से आठ बार निर्वाचित सांसद के. सुरेश भी उम्मीदवार होंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एन.डी.ए. गठबंधन ने आज एक तरह का इतिहास रचते हुए लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति चुनाव के जरिए करवाने का विकल्प चुना। एन.डी.ए. ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए कोई सर्वसम्मति बनाने के लिए विपक्ष को डैपुटी स्पीकर का पद ऑफर करने के बजाए चुनाव का रास्ता चुना।

कोटा के सांसद ओम बिड़ला ने एन.डी.ए. के सर्वसम्मति उम्मीदवार के रूप में लोकसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा। बिड़ला गत लोकसभा में भी स्पीकर रह चुके हैं।

केरल से आठ बार सांसद रह चुके कांग्रेस के के. सुरेश ने भी स्पीकर के चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा।

बिड़ला जब लोकसभा महासचिव कार्यालय में अपना नामांकन भरने गए, तब उनके साथ केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, जे.पी. नड्डा, किरण रिजीजू और एन.डी.ए. के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे।

- पहली बार कड़ा संघर्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए।
- सरकार ने संघर्ष होने की जिम्मेवारी विपक्ष पर डाली, यह कह कर कि, विपक्ष ने सर्वसम्मति से लोकसभा स्पीकर के चयन के लिए शर्त रखी थी, पर, इतने बड़े पद के लिये शर्तें लगाना उचित नहीं है, अतः सर्वसम्मति नहीं बन पायी।
- समय पूर्व राहुल गांधी व अखिलेश यादव ने कहा था कि, अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने को तैयार हो जाती है तो स्पीकर के नाम पर सर्वसम्मति बन सकती है।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इण्डिया गठबंधन से बातचीत कर रहे थे, सर्वसम्मति बनाने के लिये। विपक्ष ने घटनाक्रम पर टिप्पणी की कि, रक्षा मंत्री को अधिकार नहीं था कि, कुछ लिये-दिये की भावना से ऑफर करें, अतः सर्वसम्मति बनाने का प्रयास विफल रहा।
- इतिहास में पहली बार, स्पीकर के पद के लिये कड़ा संघर्ष वाला गंभीर चुनाव होगा, हालांकि, दो बार और इस पद पर प्रतीकात्मक चुनाव हुआ है।

बिड़ला राजस्थान के कोटा से तीसरी बार लोकसभा सांसद बने हैं।

स्पीकर पद के लिए बुधवार सुबह 11 बजे चुनाव होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष को राजी करने का काम सौंपा गया था, ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से गत रात्रि से तीन बार बात की। सूत्रों ने बताया कि सरकार विपक्ष को कोई ऑफर दिए बिना ही बातचीत की कोशिश कर रही थी। यदि कोई ऑफर दिया जाता तो सरकार और विपक्ष की दूरियों में थोड़ी कमी आती। सूत्रों ने बताया कि स्पीकर के लिए विपक्ष के समर्थन की एवज में कांग्रेस डैपुटी स्पीकर का पद मांग रही थी, लेकिन रक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एग्री युनिवर्सिटी के स्ट्राँग रूम से ओ.एम.आर. शीट गायब

जोधपुर, (कासं)। शहर के कृषि विश्वविद्यालय के स्ट्राँग रूम से जूनियर एंट्रेंस टैस्ट (जे.ई.टी.) परीक्षा की ओ.एम.आर. शीट गायब हो गई। इस बारे में जे.ई.टी. जैट समन्वयक की तरफ से मंडोर थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने इसकी जांच आरंभ कर दी है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा जैट का आयोजन दो जून को किया गया था तथा

- 2 जून को जॉइन्ट एन्ट्रेंस ट्रैस्ट (जैट) आयोजित हुआ था। कृषि विश्व विद्यालय के स्ट्राँग रूम में 333 अभ्यर्थियों की ओ.एम.आर. शीट थीं, पर 332 की ही मिलीं, एक शीट गायब थी।

जोधपुर, जयपुर, कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर के कुल 94 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन हुआ था। कोटा के विद्याश्रम स्कूल नया नोहरा बारा रोड में भी यह परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद सभी केंद्राधीक्षकों की तरफ से ओ.एम.आर. शीट को सील बंद का संबंधित जगहों पर भेजा गया था। परीक्षा का परिणाम 5 जून को तैयार किया जाना था। जब कोटा के विद्याश्रम स्कूल की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आंध्र प्रदेश ने अभी तक माफ नहीं किया है कांग्रेस को प्रदेश के विभाजन के लिये

आंध्र वासियों का मानना है कि, विभाजन के बाद आज भी आंध्र की अपनी राजधानी नहीं है, और सारे धंधे व व्यापार की दुर्गति हुई है

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। आंध्र प्रदेश की जनता कांग्रेस से अभी तक इसलिए नाराज़ है क्योंकि उसने प्रदेश का बंटवारा किया था और इसे आर्थिक संकट में डाल दिया क्योंकि आई.टी. हब एवं औद्योगिक केन्द्र हैदराबाद तेलंगाना को मिल गया और आंध्र को नुकसान हो गया। इसलिए जब से विभाजित आंध्र प्रदेश ने अपने प्रतिनिधियों को चुनना शुरु किया है उसने क्रोधवश कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया है।

हालांकि, कांग्रेस अपने आपको तेलंगाना के तेलुगू भाषी प्रदेश में पुर्नजीवित करने में सफल हुई। इसका श्रेय जाता है के. चन्द्रशेखर राव के शासन के तरीके व सरकार के कुशासन से उपजी भयंकर सरकार-विरोधी लहर को पर आंध्र प्रदेश में मतदाताओं ने कांग्रेस को नोटा से कुछ ही अधिक वोट दिए हैं। पार्टी को कम से कम इस बात के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए कि उसे

- यह क्रोध ही कारण है कि, आंध्र में हाल ही में हुए लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने धूल चाटी।
- कांग्रेस को ''नोटा'' विकल्प से कुछ ही ज्यादा मत प्राप्त हुए आंध्र में।
- पूर्व मु.मंत्री वाय.एस.आर. रेड्डी की बेटी शर्मीला भी आंध्र में कांग्रेस को कुछ ''रिलीफ'' नहीं दिला पायी हैं।
- प्रदेशाध्यक्ष शर्मीला को कांग्रेस के दयनीय प्रदर्शन के लिये जब जिम्मेवार ठहराया गया और इसके बारे में आलाकमान को पत्र लिखा तो शर्मीला ने शिकायत करने वाले प्रदेश कार्यालय में प्रवेश से वर्जित कर दिया तथा कांग्रेस को और उपहास का पात्र बनाया आंध्र प्रदेश में।

नोटा से कम वोट प्राप्त नहीं हुए, नोटा का प्रतिशत 1.09 तथा जबकि इसकी तुलना में कांग्रेस का वोट शेयर 1.72 प्रतिशत रहा है यह वोट प्रतिशत हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनावों एवं प्रदेश की विधानसभा चुनावों के नतीजों में रहा है। इस स्थिति को देखा जाए तो यह तकनीकी रूप से इस बार 2019 के चुनावों की तुलना में कुछ सुधार ही हुआ है क्योंकि तब कांग्रेस को (1.17 प्रतिशत) मत मिले थे जो कि आंध्र प्रदेश में नोटा को डाले गए 1.28 प्रतिशत मतों से भी कम थे।

यहाँ तक कि शक्तिशाली वाय.एस. राजशेखर रेड्डी की बेटी और मुख्यमंत्री

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इण्डिया गठबंधन नये सहयोगियों की तलाश में निकली

नवीन पटनायक की पार्टी बी.जे.डी. के बाद, आंध्र की वाय.एस.आर. कांग्रेस भी एन.डी.ए. से निराश होकर, नये ठिकाने (इण्डिया गठबंधन) की ओर देखने लगी है

-श्रीनदं झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। बीजू जनता दल (बी.जे.डी.) अध्यक्ष नवीन पटनायक का यह निर्णय कि वे राज्यसभा में विपक्ष का समर्थन करेंगे, यह इस कहावत को चरितार्थ करता है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र अथवा दुश्मन नहीं होता है।

जबकि, ओडिशा में बी.जे.डी. एवं आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की वाय.एस.आर.सी.पी. दोनों राजनीतिक पार्टियाँ एन.डी.ए. की सदस्य नहीं थी, पर इन पार्टियों ने नरेन्द्र मोदी के पहले व दूसरे कार्यकाल में राज्यसभा में भाजपा सरकार को बार-बार बचाया था।

विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भाजपा के हाथों करारी हार झेलने के बाद समीकरण अब बदल रहे हैं।

चूंकि, बी.जे.डी. हाल ही में सम्पन्न लोकसभा चुनावों में एक भी लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने में विफल रही है और विधानसभा में इस पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर मात्र 58 रह गई है जबकि इसके विपरीत भाजपा ने 78 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी और उसने वहां सरकार का गठन कर लिया। लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बी.जे.डी. के अभी नौ सांसद हैं।

- बी.जे.डी. व वाय.एस.आर. कांग्रेस के ज्यादा सांसद नहीं है, लोकसभा में, पर, राज्यसभा में बी.जे.डी. के 9 सांसद व वाय.एस.आर. कांग्रेस के ग्यारह सदस्य हैं। अतः, कांग्रेस भी इन दोनों पार्टियों का राज्यसभा में सहयोग व समर्थन पाने के लिये काफी लालायित है।

बी.जे.डी. अब प्रदेश में ''मजबूत व जीवंत विपक्ष'' की भूमिका निभाएगी'' और पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने कहा कि ''उनकी पार्टी राज्यसभा में विपक्ष का भी समर्थन करेगी।''

पटनायक ने यह भी कहा कि ''संसद में बी.जे.डी. ओडिशा के लिए मजबूत आवाज़ उठाएगी और संसद में राज्य से संबंधित मुद्दों को तत्परता से उठाएगी।''

यह कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र अथवा दुश्मन नहीं होता है, इसका आगामी महीनों में विस्तार होने की संभावना है जैसा कि हाल ही में गठबंधन के दलों ने यह संकेत देना शुरु कर दिय है अपने प्रदेश में अपनी स्थिति की समीक्षा के बाद ऐसे प्रदेश में महाराष्ट्र भी है।

आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में सम्पन्न विधानसभा व संसद के चुनावों में वाय.एस.आर.सी.पी. का सूपड़ा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'रिटायर्ड आई.एफ.एस. के वेतन में इन्क्रीमैंट का मसला एक माह में तय करे सरकार'

जयपुर, 25 जून। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने छह साल पहले तीस जून को रिटायर हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर सरकार को

- केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 30 जून 2018 को कोटा से रिटायर हुए आई.एफ.एस. अफसर ललित सिंह को 30 जून 2017 से 30 जून 2018 तक की वेतन वृद्धि नहीं दिए जाने पर सरकार को आदेश दिए।

कहा है कि, वह प्रकरण का एक माह में निस्तारण लक्ष्मण प्रसाद के मामले में दिए फैसले के तहत करे। अधिकरण ने कहा है कि, इस संबंध में पेश याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय किया जाए। अधिकरण ने ये आदेश ललित सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि, याचिकाकर्ता 30 जून, 2018 को कोटा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज रिहा हुए

12 साल तक लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें लंदन की हाई सिक्यूरिटी जेल से रिहा किया गया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जून। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के लंदन की एक हाईसिक्योरिटी जेल से रिहा होने के साथ ही ''प्रैस फ्रीडम'' से संबंधित 21 वीं सदी का सबसे मशहूर कानूनी के केस आज प्रकट रुप से समाप्त हो गया।

असांज 12 वर्षों तक कैद में रहे। इस दौरान उन्होंने स्वयं को अमेरिका प्रत्यार्पित किए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाईयां भी लड़ी। इन 12 वर्षों में से 7 वर्ष तो उन्होंने लंदन स्थित इक्वेडोर दूतावास में बिताए और 5 साल ब्रिटेन की एक हाईसिक्योरिटी जेल में।

अमेरिका अपने गुप्त सैन्य दस्तावेजों के प्रकाशन को लेकर असांज को अपने यहां प्रत्यर्पित करवाना चाहता था। असांज ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। जूलियन असांज ने इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्धों से संबंधित 5 लाख गुप्त दस्तावेजों का प्रकाशन किया था। इन दस्तावेजों के

- असांज वर्ष 2017 में एकाएक सुर्खियों में आए जब उन्होंने अमेरिका के इरॉक युद्ध व अफगानिस्तान वॉर से संबंधित 5 लाख गोपनीय दस्तावेज़ सार्वजनिक कर दिए।
- इससे आग बबूला अमेरिका ने असांज की गिरफ्तारी और उसे अमेरिका के सुपुर्द करने पर जोर दिया, इस अपराध के लिए अमेरिका में उन्हें 175 साल की सजा हो जाती।
- पर, दुनिया भर के मानवाधिकार एवं आज़ादी समर्थक संगठनों ने अमेरिका का विरोध किया।
- असांज ने लंदन के इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली और यूरोपियन ह्यूमन राइट्स लॉ के तहत अपील की। उनका केस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रैस की आज़ादी के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया था।

सार्वजनिक हो जाने के बाद अमेरिका के आचरण को लेकर भारी विवाद छिड़ गया था और असांज ने दावे से कहा था कि ''इससे साबित होता है कि अमेरिका ने युद्ध अपराध किए हैं।''

इससे क्रोधित अमेरिका ने मांग की थी कि, असांज को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए उसके यहां भेजा जाए। असांज को गिरफ्तार कर यदि अमेरिका लाया जाता तो उन्हें तकरीबन 175 वर्ष के कारावास की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जायेंगे

नई दिल्ली, 25 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जा सकते हैं। खुद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। क्रेमलिन ने मंगलवार को घोषणा की कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन के विदेश मामलों के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा कि, भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी की जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। अगर दौरा होता है तो

- रुस के राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी देते हुये बताया कि, प्र.मंत्री मोदी की रूस यात्रा की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं।

करीब पांच वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला रूस दौरा होगा। मोदी ने सितंबर 2019 में रूस का दौरा किया था। उशाकोव ने कहा कि तारीख की घोषणा बाद में संयुक्त रूप से की जाएगी। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी की संभावित यात्रा पर भारतीय पक्ष की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। पीएम मोदी आखिरी बार 2019 में रूस के दौरा पर गए थे। हालांकि अब पीएम मोदी की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मु.मंत्री भजनलाल ने राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की

मु.मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि, समिट में होने वाले विभिन्न एम.ओ.यू. को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए अमल में लाया जाए

जयपुर, 25 जून (का.सं.)। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट-2024, की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि, राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार निवेशकों के लिए हर स्तर पर मदद कर अनुकूल वातावरण तैयार करेगी जिससे देश-विदेश से अधिकतम निवेश राज्य में आएं तथा राजस्थान देश में सबसे बड़े ''इन्वैस्टमैंट हब'' के रूप में उभरे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट-2024, के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से जुट जाएं तथा इस ऐतिहासिक आयोजन की प्रत्येक गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि, समिट में होने वाले विभिन्न एम.ओ.यू. को केवल कागजों पर ही न रखकर धरातल पर उतारा जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि, सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ इस आयोजन का भव्य क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि, समिट में आने वाले निवेशकों के आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि, प्रचार-प्रसार किसी भी आयोजन की सफलता का मुख्य आधार होता है। अधिकारी प्रचार-प्रसार के लिए बेहतरीन कार्ययोजना बनाएं जिससे वैश्विक स्तर पर यह आयोजन चर्चा का विषय बने।

शर्मा ने कहा कि, सभी उद्योगों को एक ही छत के नीचे निवेश संबंधी सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए सिंगल विंडो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सिंगल विंडो के लिए विभाग द्वारा अलग से पूरा सिस्टम तैयार किया जाए जिससे उद्यमियों को निवेश में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, संसाधनों का समुचित उपयोग कर निवेश संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

- मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारे राजस्थान को देश के सबसे बड़े इन्वैस्टमैंट हब के रूप में उभारना है और इसके लिए निवेश को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि, राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट-2024,का भारी प्रचार किया जाए, क्योंकि, प्रचार प्रसार ही आयोजन की सफलता का मुख्य आधार होता है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि, समिट में प्रवासी राजस्थानियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- बैठक में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, उद्योग राज्यमंत्री के.के. विश्नोई, मुख्य सचिव सुधांश पंत व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मु. मंत्री भजनलाल शर्मा ने सी.एम. ऑफिस में राजस्थान इन्वैस्टमैंट समिट-2024 की तैयारियों के संदर्भ में अयोजित समीक्षा बैठक में उच्च अधिकारियों से बातचीत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, राजस्थान के प्रवासी विश्व के प्रत्येक हिस्से में मौजूद हैं तथा वे अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान के प्रवासी प्रदेश में निवेश के लिए हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि, समिट में प्रवासी राजस्थानियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए, उनके लिए अलग से सत्र आयोजित हों जिससे वे अपने राज्य में निवेश कर राज्य को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाने में अपनी महती भूमिका निभा सकें।

बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से इन्वैस्टमैंट समिट की गतिविधियां, मुख्य समारोह का प्रारूप, वित्त, उद्योग, परिवहन, पर्यटन, जेडीए, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग सहित विभिन्न विभागों की भूमिका, नवीन प्रस्तावित नीतियां,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल को सी.बी.आई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 25 जून। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को

- सी.बी.आई. ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत याचिका से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को तिहाड़ जेल में ही सी.बी.आई. ने केजरीवाल से पूछताछ की और तभी उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला लिया।

सी.बी.आई. ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया है। ई.डी. मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)